International Journal Of Multidisciplinary Research In Science, Engineering And Technology (IJMRSET)

Volume 2, Issue 12, December 2019

भारत के पड़ोसी देश के साथ संबंध: चीन के साथ संबंधो के विशेष संदर्भ में

Dr. Dhiraj Bakolia

Associate Professor, Dept. of Political Science, Govt. Lohia College, Churu, Rajasthan, India

सार

हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने मालदीव के राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा कि भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और मालदीव की 'इंडिया फर्स्ट' नीति विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए एक-दूसरे की पूरक है।

भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति:

- परिचय:
  - अपनी 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत भारत अपने सभी पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध विकसित करने के लिये प्रतिबद्ध है।
    - भारत एक सक्रिय विकास भागीदार है और इन देशों में कई परियोजनाओं में शामिल है।
  - भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति स्थिरता और समृद्धि के लिये पारस्परिक रूप से लाभप्रद, जन-उन्मुख, क्षेत्रीय ढाँचे के निर्माण पर केंद्रित है।
  - इन देशों के साथ भारत का जुड़ाव एक परामर्शी, गैर-पारस्परिक और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण पर आधारित है, जो अधिक-से-अधिक कनेक्टिविटी, बेहतर बुनियादी ढाँचे, विभिन्न क्षेत्रों में मज़बूत विकास सहयोग, सुरक्षा और व्यापक जन-समूह संपर्क जैसे लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है।
- उद्देश्य:
  - कनेक्टिविटी:
    - भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SAARC) के सदस्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।
    - ये समझौते सीमा पार संसाधनों, ऊर्जा, माल, श्रम और सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं।
  - पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार:
    - पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार करना भारत की प्राथमिकताओं में शामिल है, क्योंकि विकास के एजेंडे को साकार करने के लिये दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग आवश्यक है।
  - वार्ता:
    - यह पड़ोसी देशों के साथ संबंध स्थापित कर और वार्ताओं के माध्यम से राजनीतिक संपर्क का निर्माण करके क्षेत्रीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - आर्थिक सहयोग:
    - यह पड़ोसियों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने पर केंद्रित है।
      - भारत ने इस क्षेत्र में विकास के उद्देश्य से SAARC सम्मेलनों में भाग लिया तथा इसके सदस्य देशों की ढाँचागत परियोजनाओं में निवेश किया है।

- उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते (MVA),जल शक्ति प्रबंधन और इंटर-ग्रिड कनेक्टिविटी में भारत की भागीदारी को देखा जा सकता है।

- आपदा प्रबंधन:
  - यह नीति आपदा प्रतिक्रिया, संसाधन प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और संचार पर सहयोग करने तथा सभी दक्षिण एशियाई नागरिकों के लिये आपदा प्रबंधन में क्षमताओं और विशेषज्ञता पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- सैन्य और रक्षा सहयोग:
  - भारत विभिन्न रक्षा अभ्यासों के आयोजन में भाग लेकर सैन्य सहयोग के माध्यम से क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।

पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध:

- भारत-मालदीव:
  - सुरक्षा साझेदारी:
    - हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने मालदीव की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (NCPLE) का उद्घाटन किया था।.
  - पुनर्सुधार केंद्र:
    - 'अड्डू रिक्लेमेशन एंड शोर प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट' (Addu Reclamation and Shore Protection Project) हेतु 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
    - अड्डू में एक 'ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर' (Drug Detoxification And Rehabilitation Centre) का निर्माण भारत की मदद से किया गया है।
      - यह सेंटर/केंद्र स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्यपालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है।
  - आर्थिक सहयोग:
    - पर्यटन, मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वर्तमान में मालदीव कुछ भारतीयों के लिये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और कई भारतीय वहाँ रोज़गार के लिये जाते हैं।
    - एक भारतीय कंपनी, 'एफकॉन' (Afcons) ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजना- ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे।
- भारत - भूटान:
  - भारत-भूटान शांति और मित्रता संधि, 1949:
    - यह संधि अन्य बातों के अलावा स्थायी शांति तथा मित्रता, मुक्त व्यापार तथा वाणिज्य और एक-दूसरे के नागरिकों को समान न्याय प्रदान करने पर ज़ोर देती है।
      - इस संधि को वर्ष 2007 में संशोधित किया गया, जिसमें भारत द्वारा भूटान को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित करने के लिये प्रेरित किया गया।
  - जलविद्युत सहयोग:
    - यह वर्ष 2006 के जलविद्युत सहयोग समझौते के अंतर्गत आता है।
      - इस समझौते के एक प्रोटोकॉल के तहत भारत भूटान को न्यूनतम 10,000 मेगावाट जलविद्युत के विकास एवं उसी से अधिशेष बिजली आयात करने पर सहमति व्यक्त की है।
  - आर्थिक सहायता:

- भारत, भूटान के विकास में प्रमुख भागीदार देश है।
- वर्ष 1961 में भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना (FYP) के शुभारंभ के बाद से भारत, भूटान की FYPs के लिये वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
- भारत ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2018-23) के लिये 4500 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं।

- भारत - नेपाल:
  - उच्च स्तरीय दौरा:
    - हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी, नेपाल का दौरा किया , जहाँ उन्होंने भारतीय सहायता से बनाए जा रहे बौद्ध विहार की नेपाली प्रधानमंत्री के साथ आधारशिला रखी।
  - वर्ष 1950 की शांति और मित्रता की संधि:
    - संधि दोनों देशों में निवास, संपत्ति, व्यापार और आवाज़ाही के लिये भारतीय और नेपाली नागरिकों के पारस्परिक व्यवहार के बारे में बात करती है।
      - यह भारतीय और नेपाली दोनों व्यवसायों के लिये राष्ट्रीय व्यवहार भी स्थापित करता है (अर्थात्- एक बार आयात किये जाने के बाद विदेशी वस्तुओं को घरेलू सामानों से अलग नहीं माना जाएगा)।
  - जल विद्युत परियोजनाएँ:
    - दोनों देशों ने 490.2 मेगावाट के अरुण-4 जलविद्युत परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिये सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के बीच पाँच समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
      - नेपाल ने भारतीय कंपनियों को नेपाल में पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना में निवेश करने के लिये भी आमंत्रित किया।

- भारत - श्रीलंका:
  - हाइब्रिड पावर:
    - भारत और श्रीलंका ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, जिसने भारत को जाफना के तीन द्वीपों (नैनातिवु, डेल्फ़्ट या नेदुन्थीवु, और एनालाइटिवू) में हाइब्रिड विद्युत परियोजनाएँ स्थापित करने की सुविधा प्रदान की।
  - समुद्री बचाव समन्वय केंद्र:
    - भारत और श्रीलंका एक समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC) स्थापित करने पर भी सहमत हुए हैं, जो पड़ोसियों के बीच अधिक रक्षा क्षेत्र सहयोग का संकेत देता है।
  - 'एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क'
    - भारत ने श्रीलंका को 'एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क' को लागू करने के लिये अनुदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, जो मुख्य तौर पर 'आधार कार्ड' प्रणाली पर आधारित है।
      - 'एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क' भारत की 'आधार' प्रणाली के समान है और इसके तहत श्रीलंका निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा:
        - बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण।
        - डिजिटल उपकरण, जो साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान करते हों।
        - 'व्यक्तिगत पहचान' प्रणाली, जिसे दो उपकरणों के संयोजन से डिजिटल एवं भौतिक वातावरण में सटीक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।

भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के समक्ष चुनौतियाँ :

- चीन का बढ़ता दबाव:
  - यह एक सार्थक कदम उठा पाने में विफल रहा तथा बढ़ते चीनी दबाव ने देश को इस क्षेत्र में सहयोगी बनने से रोक दिया है।
    - समुद्री मोर्चे पर चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।
- घरेलू मामलों में हस्तक्षेप:
  - भारत पड़ोसी देशों खासकर नेपाल के घरेलू मामलों में उनकी संप्रभुता के उल्लंघन में दखल दे रहा है।
    - भारत नेपाल के भीतर और बाहर मुक्त पारगमन और मुक्त व्यापार में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है तथा लोगों और सरकार पर दबाव बनाता रहता है।
- भारत की घरेलू राजनीति का प्रभाव:
  - भारत की घरेलू नीतियाँ मुस्लिम बहुल देश बांग्लादेश में समस्याएँ पैदा कर रही हैं, यह दर्शाती है कि भारत की पड़ोस पहले की नीति बांग्लादेश जैसे मित्र क्षेत्रों में भी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।
- पश्चिमी देशों की ओर भारत के झुकाव का प्रभाव:
  - भारत विशेष रूप से क्वाड और अन्य बहुपक्षीय और लघु-पार्श्व पहलों के माध्यम से पश्चिम के करीब आता है।
    - लेकिन पश्चिम के साथ श्रीलंका के संबंध अच्छी दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि देश की वर्तमान सरकार को मानवाधिकारों के मुद्दों और स्वतंत्रता पर पश्चिमी राजधानियों/देशों से बढ़ती आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

आगे की राह

- भारत की पड़ोस नीति गुजराल सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिये।
  - इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत के कद और ताकत को उसके पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों की गुणवत्ता से अलग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे क्षेत्रीय विकास संभव हो पाता है।
- भारत की क्षेत्रीय आर्थिक और विदेश नीति को एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
  - इसलिये भारत को छोटे आर्थिक हितों के लिये पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों से समझौता करने का विरोध करना चाहिये।
- क्षेत्रीय संपर्क को अधिक मज़बूती के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिये जबकि सुरक्षा चिंताओं को लागत प्रभावी, कुशल और विश्वसनीय तकनीकी उपायों के माध्यम से संबोधित किया जाता है जो दुनिया के अन्य हिस्सों में उपयोग में हैं।

परिचय

भारत-चीन दोनों पड़ोसी एवं विश्व के दो उभरती शक्तियाँ हैं। दोनों के बीच लम्बी सीमा-रेखा है।

इन दोनों में प्रचीन काल से ही सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ है। चीन के लोगों ने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों अर्थात् नालन्दा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय को चुना था क्योंकि उस समय संसार में अपने तरह के यही दो विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। उस काल में यूरोप के लोग जंगली अवस्था में थे।

यद्यपि 1946 में चीन के साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तदपि दोनों देशों के बीच मैत्री सम्बन्ध बराबर बने रहे। चीन के संघर्ष के प्रति भारत द्वारा विकासशील देश नीति की गई एवं पंचशील पर आस्था भी प्रकट की गई। वर्ष 1949 में नये चीन की स्थापना के बाद के अगले वर्ष, भारत ने चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये। इस तरह भारत, चीन लोक गणराज्य को मान्यता देने वाला प्रथम गैर-समाजवादी देश बना।

वर्ष 1954 के जून माह में चीन, भारत व म्यान्मार द्वारा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धान्त यानी पंचशील प्रवर्तित किये गये। पंचशील चीन व भारत द्वारा दुनिया की शान्ति व सुरक्षा में किया गया एक महत्वपूर्ण योगदान था, और आज तक दोनों देशों की

जनता की जबान पर है। देशों के सम्बन्धों को लेकर स्थापित इन सिद्धान्तों की मुख्य विषयवस्तु है- एक-दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखण्डता का सम्मान किया जाये, एक-दूसरे पर आक्रमण न किया जाये, एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाये और समानता व आपसी लाभ के आधार पर शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व बरकारार रखा जाये।

परन्तु चीन नें मैत्री सम्बन्धों को ताख पर रख कर 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत की बहुत सारी भूमि पर कब्जा करते हुए 21 नवम्बर 1962 को एकपक्षीय युद्धविराम की घोषणा कर दी। उस समय से दोनों देशों के सम्बन्ध आज-तक सामान्य नहीं हो पाए हैं।

जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने चीन से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, परन्तु भारत को सफलता नहीं मिली, क्योंकि चीन ने 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अन्यायपूर्ण ढँग से पाकिस्तान का एकतरफा सर्मथन किया था। 23 सितम्बर 1965 को भारत-पाकिस्तान युद्धविराम का समझौता हो गया। अतः चीन के सारे इरादों पर पानी फिर गया।

पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन को काराकोरम क्षेत्र में बसा दिया एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का 2,600 वर्ग मील भू–भाग चीन को सौंप दिया। जिससें चीन के साम्यवादी दल के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता एवं चीन के राष्ट्रपति जियांग जोमीन ने नवम्बर 1966 में तीन दिन की भारत यात्रा की थी। यह चीन के राष्ट्रपति द्वारा की गई पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान एक एतिहासिक समझौता किया गया, जिसके अर्न्तगत वास्तविक नियन्त्रण रेखा पर एक दूसरे द्वारा आक्रमण नही करने का वचन दिया गया। दोनों देशों ने अपने सैनिक बल का प्रयोग न करने का एवं हिमालय की झगड़े वाली सीमा पर शान्ति व्यवस्था बनायें रखने का समझौता किया। इस यात्रा के समय 11 सूत्रीय समझौता किया गया। अक्टूबर 1967 में भारत और चीन के मध्य तेल एवं गैस को प्राप्ति करने की भागीदारी के लिए एक समझौता किया गया था।

70 के दशक के मध्य तक भारत और चीन के सम्बन्ध शीत काल से निकल कर फिर एक बार घनिष्ठ हुए। जनवरी 1980 से चीन ने कुछ नरमी प्रदर्शित की जिसके फलस्वरूप भारत-चीन सम्बन्धों में सुधार की आशा व्यक्त की गई।

सन् 1998 में दोनों देशों के मध्य पुनः तनाव पैदा हो गया। भारत ने 11 से 13 मई 1998 के मध्य पाँच परमाणु परीक्षण कर अपने आप को शस्त्र धारक देश घोषित किया था। इसी दौरान भारत के रक्षामन्त्री रहें श्री जार्ज फर्नाण्डीस ने चीन को भारत का सबसे बड़ा शत्रु की संज्ञा दे डाली थी जिसने चीन की मानसिकता अचानक परिवर्तित हो गयी। चीन ने अमेरिका एवं अन्य देशों के साथ मिलकर एन०पी०टी० एवं सी०टी०बी०टी० पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत को बाध्य करना प्रारम्भ कर दिया। 5 जून 1998 को चीन के द्वारा दबाव बनाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा परीक्षण बन्द करने, शस्त्र विकास कार्यक्रम बन्द करने एवं सी०टी०बी०टी० पर तथा एन०पी०टी० पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव पास करा दिया। जुलाई 1998 में एशियान रीजनल फोरम की बैठक में विदेश मन्त्री जसवंत सिंह एवं चीन के विदेश मन्त्री तांग जियाशं के मध्य वार्ता हुई। दोनों ने उच्च सरकारी विचार-विर्मश को जारी रखने का निर्णय लिया। अक्टूबर 1998 में चीन ने अटल बिहारी वाजपेयी को दलाई लामा के साथ मुलाकात की आलोचना की और इसे 'चीन के विरूद्ध तिब्बत-कार्ड का प्रयोग' कहा। फरवरी 1996 को भारत ने सम्बन्धों में मिठास लाने की पहल करते हुए एक मन्त्रालय-स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल वार्षिक विचार विर्मश के लिए भेजा। चीन के रूख को भारतीय मन्त्रालय ने अपने हित में नहीं पाया। चीन ने इसे अवश्य सकरात्मक एवं प्रगतिवादी दृष्टिकोण का नाम दिया।

अप्रैल 1996 में साझे कार्यसमूह की बीजिंग में 11वीं बैठक हुई जिसमें दोनों देशों में विकास के नये पहलुओं पर जोरदार चर्चा हुई। एक बार पुनः दोनो देशों के मध्य सम्बन्धों में सुधार के आसार दिखने लगे। जून 1996 में भारतीय विदेश मन्त्री जसवन्त सिहं ने चीन की यात्रा पर वहाँ के नेताओं से उच्चस्तरीय वार्तालाप की दोनो देशों के मध्य परस्पर आर्थिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक सहयोग विकसित करने की दिशा में आगे कदम उठाने का निर्णय लिया गया, भारत-चीन के व्यापार को 2 अरब डॉलर से अधिक बढ़ाने व साझे कार्यसमूह की गतिविधियों में वृद्धि के लिए भी निर्णय लिया गया। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान को दोषी ठहराते हुए फरवरी 2000 में भारत ने चीन की डब्लू टी०ओ० सदस्यता प्राप्त करने के लिए सर्मथन किया था। मार्च 2000 में भारत एवं चीन के मध्य वीजिंग में सुरक्षा वार्तालाप का पहला दौर प्रारम्भ हुआ जो सचिव-स्तरीय था। सुरक्षा वार्तालाप दो दिनों तक चला। इस कार्यक्रम में चीन ने भारत को सी०टी०बी०टी० पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मई 2000 में भारत के राष्ट्रपति के० आर० नारायणन ने चीन की यात्रा कर दोनों देशों के सभी हितकर मुद्दे पर वार्तालाप की भारत व चीन नें द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापार सम्बन्धों में वृद्धि करने के लिए प्रयास करने की प्रतिबद्धता प्रकट की, लेकिन सीमा विवाद पर कोई निष्कर्षजन्य बात नहीं हो पायी।

वर्ष 2001 में पूर्व चीनी नेता ली फंग ने भारत की यात्रा की। वर्ष 2002 में पूर्व चीनी प्रधानमंत्री जू रोंग जी ने भारत की यात्रा की। इस के बाद, वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमन्त्री वाजपेयी ने चीन की यात्रा की। उन्होंने चीनी प्रधानमन्त्री वन चा पाओ के साथ चीन-भारत सम्बन्धों के सिद्धान्त और चतुर्मुखी सहयोग के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये। इस घोषणापत्र ने जाहिर किया कि चीन व भारत के द्विपक्षीय सम्बन्ध अपेक्षाकृत परिपक्व काल में प्रवेश कर चुके हैं। इस घोषणापत्र ने अनेक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समस्याओं व क्षेत्रीय समस्याओं पर दोनों के समान रुख भी स्पष्ट किये। इसे भावी द्विपक्षीय सम्बन्धों के विकास का निर्देशन करने वाला मील के पत्थर की हैसियत वाला दस्तावेज भी माना गया।

चीन के प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ ने 2005 और 2010 में भारत की यात्रा की। चीनी राष्ट्रपति हू जिन्ताओ 2006 में भारत आये थे। भारतीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने सन 2008 में चीन की यात्रा की। चीन के प्रधानमन्त्री ली ख छ्यांग 2013 में भारत आये। इसके अलावा ब्रिक्स शिखर बैठक से जुड़ी दो बैठकें भी हुईं: डा. मनमोहन सिंह ने 2011 में सान्या, चीन का दौरा किया तथा राष्ट्रपति हू जिन्ताओ ने 2012 में नई दिल्ली का दौरा किया तथा एक यात्रा अक्टूबर, 2008 में असेम शिखर बैठक के सिलसिले में बीजिंग की हुई।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारत एवं चीन के मध्य प्राचीन काल से चली आ रही मैत्री आधुनिक काल में कई अस्थिर दौरों से गुजरती रही है। भारत और चीन का सीमा विवाद आज तक बना हुआ है। हालांकि इधर चीन व भारत के सम्बन्धों में भारी सुधार हुआ है, तो भी दोनों के सम्बन्धों में कुछ अनसुलझी समस्याएँ रही हैं। चीन व भारत के बीच सब से बड़ी समस्याएँ सीमा विवाद और तिब्बत की हैं। चीन सरकार हमेशा से तिब्बत की समस्या को बड़ा महत्व देती आई है।

इस समय चीन व भारत अपने-अपने शान्तिपूर्ण विकास में लगे हैं। 21वीं शताब्दी के चीन व भारत प्रतिद्वन्दी हैं और मित्र भी।

विचार-विमर्श

2014 में नरेन्द्र मोदी जब भारत के प्रधानमन्त्री बने तो पूरा देश उनमें भारत के लिए कई संभावनाएं देख रहा था। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध को लेकर भी देश के लोगों को काफी उम्मीद थी। नरेन्द्र मोदी ने शुरुआत में अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में काफी प्रयास भी किए। इसी कड़ी में सितम्बर 2014 को चीन के राष्ट्रपति मोदी के निमंत्रण पर अहमदाबाद पहुंचे।

जिस तरह से मोदी ने उनकी आगवानी की, उससे लगा कि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध सुधरेगा। इस यात्रा के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग और रेलवे में सहयोग समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा दोनों देशों ने क्षेत्रीय मुद्दों और चीन के औद्योगिक पार्क से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हालांकि उसी दौरान चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के करीब 1000 जवान पहाड़ी से जम्मू कश्मीर के चुमार क्षेत्र में घुस आए थे। भारत ने चीनी राष्ट्रपति के सामने यह मुद्दा उठाया लेकिन अपनी तरफ से वार्ता में कोई खलल नहीं पड़ने दिया।

18 जून साल 2017 को डोकलाम पर सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनाव शुरू हुआ और यह लगभग 73 दिनों तक चला। ध्यातव्य है कि भारत-भूटान और चीन को मिलाने वाला बिन्दु को भारत में डोकलाम, भूटान में 'डोक ला' और चीन में 'डोकलांक' कहा जाता है। डोकलाम एक पठार है जो भूटान के हा घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला, और चीन के यदोंग काउंटी के बीच में है।

डोकलाम का कुछ हिस्सा सिक्किम में भारतीय सीमा से सटी हुई है, जहां चीन सड़क बनाना चाहता है। भारतीय सेना ने सड़क बनाए जाने का विरोध किया। भारत की चिन्ता यह है कि अगर यह सड़क बनी तो हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी कड़ी यानी 'मुर्गी की गरदन' जैसे इस इलाके पर चीन की पहुंच बढ़ जाएगी। वहीं चीन ने अपनी सम्प्रभुता की बात दोहराते हुए कहा कि उन्होंने सड़क अपने इलाके में बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने भारत भारतीय सेना पर "अतिक्रमण" का आरोप लगाया।

चीन का कहना था कि भारत 1962 में हुई हार को याद रखे। चीन ने भारत को चेतावनी भी दी कि चीन पहले भी अधिक शक्तिशाली था और अब भी है। जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन समझे की अब समय बदल गया है, यह 2017 है। इस विवाद का असर यह हुआ कि चीन ने भारत से कैलाश के लिए जाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों को मानसरोवर यात्रा पर जाने से रोक दिया। हालांकि बाद में चीन ने हिमाचल प्रदेश के रास्ते 56 हिंदू तीर्थयात्रियों को मनसरोवर यात्रा के लिए आगे जाने की अनुमति दे दी। डोकलाम पर भारत-चीन के बीच लगभग दो महीने तक काफी तनातनी होने के बाद अन्ततः विवाद समाप्त हुआ।

चीन और भारत के बीच अरबों डॉलर का व्यापार है। 2008 में चीन भारत का सबसे बड़ा बिज़नेस पार्टनर बन गया था। 2014 में चीन ने भारत में 116 बिलियन डॉलर का निवेश किया जो २०१७ में 160 बिलियन डॉलर हो गया। 2018 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 88 अरब डॉलर रहा। यह बात महत्वपूर्ण है कि पहली बार भारत, चीन के साथ व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर तक कम करने में सफल रहा।

चीन वर्तमान में भारतीय उत्पादों का तीसरी बड़ा निर्यात बाजार है। वहीं चीन से भारत सबसे ज्यादा आयात करता है और भारत, चीन के लिए उभरता हुआ बाज़ार है। चीन से भारत मुख्यतः इलेक्ट्रिक उपकरण, मेकेनिकल सामान, कार्बनिक रसायनों आदि का आयात करता है। वहीं भारत से चीन को मुख्य रूप से, खनिज ईंधन और कपास आदि का निर्यात किया जाता है। भारत में चीनी टेलिकॉम कंपनियाँ 1999 से ही हैं और वे काफी पैसा कमा रही हैं। इनसे भारत को भी लाभ हुआ है। भारत में चीनी मोबाइल का मार्केट भी बहुत बड़ा है। चीन दिल्ली मेट्रो में भी लगा हुआ है। दिल्ली मेट्रो में एसयूजीसी (शंघाई अर्बन ग्रुप कॉर्पोरेशन) नाम की

कंपनी काम कर रही है। भारतीय सोलर मार्केट चीनी उत्पाद पर निर्भर है। इसका दो बिलियन डॉलर का व्यापार है। भारत का थर्मल पावर भी चीनियों पर ही निर्भर है। पावर सेक्टर के 70 से 80 फीसदी उत्पाद चीन से आते हैं। दवाओं के लिए कच्चे माल का आयात भी भारत चीन से ही करता है। इस मामले में भी भारत पूरी तरह से चीन पर निर्भर है।

2018 में भारत का व्यापार घाटा करीब 52 अरब डॉलर रहा। पिछले कई वर्षों से चीन के साथ लगातार छलांगे लगाकर बढ़ता हुआ व्यापार घाटा भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। चीन के बाजार तक भारत की अधिक पहुंच और अमेरिका व चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के कारण पिछले वर्ष भारत से चीन को निर्यात बढ़कर 18 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो वर्ष 2017-18 में 13 अरब डॉलर था। चीन से भारत का आयात भी 76 अरब डॉलर से कम होकर 70 अरब डॉलर रह गया।

27 मई, 2018 को भारत ने चीन के सॉफ्टवेयर बाजार का लाभ उठाने के लिए वहां दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) गालियारे की शुरुआत की। आईटी कंपनियों के संगठन नैसकॉम ने कहा कि चीन में दूसरे डिजिटल सहयोगपूर्ण सुयोग प्लाजा की स्थापना से चीन के बाजार में घरेलू आईटी कंपनियों की पहुंच बढ़ गयी।

परिणाम

- १९५० के पहले हजारों वर्षों तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शान्त रखा। 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे एवं कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही सीमित थे।

- भारत और चीन के मध्य व्यापक तौर पर बातचीत की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता (1947) और चीन की कम्युनिस्ट क्रांति (1949) के बाद हुई।

- 1 अप्रैल 1950 को चीन और भारत ने राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए। केएम पैनिकर को चीन में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया। भारत चीन के जनवादी गणराज्य के साथ सम्बन्ध स्थापित करने वाला पहला गैर-साम्यवादी देश था। "हिंदी चीनी भाई भाई" उस समय से एक आकर्षक कहानी बन गई है और द्विपक्षीय आदान-प्रदान प्रारम्भ हुआ।

- अक्टूबर १९५० तक चीन ने तिब्बत को लेकर इरादे जाहिर कर दिए। सीमा पार कर चीनी सेना ल्हासा की तरफ बढ़ी। 1951 में चमदो के गवर्नर को मजबूर किया गया कि वह तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार करें। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर वहाँ कब्ज़ा कर लिया तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और 'पड़ोसी देश' बन गए।

- भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्र तिब्बत के पक्ष में थे। उल्लेखनीय है कि भारत और तिब्बत के मध्य आध्यात्मिक सम्बन्ध चीन के लिये चिन्ता का विषय था।

- मई 1954 में, चीनी प्रधानमंत्री झोउ एनलाई ने भारत का दौरा किया। चीन और भारत ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व (पंचशील) के पांच सिद्धांतों की संयुक्त रूप से वकालत की। उसी वर्ष, भारतीय प्रधान मंत्री नेहरू ने चीन का दौरा किया। वह एक गैर-साम्यवादी देश की सरकार के पहले प्रमुख थे जिन्होंने 'पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना' की स्थापना के बाद से चीन का दौरा किया।

- साल भर भी नहीं बीते थे कि चीन ने इन्हीं सिद्धान्तों का उल्लंघन किया। अपने आधिकारिक मानचित्र में चीन ने भारत की उत्तरी सीमा के एक हिस्से को अपना बताना शुरू किया।

- नवम्बर 1956 में चीन के तत्कालीन शासक झोउ एनलाई भारत आए।

- सितम्बर 1957 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीन गए।

- इसी बीच सम्बन्ध बिगड़ने लगे। चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना हक जताना शुरू कर दिया था। झोउ ने 23 जनवरी, 1959 को कहा कि लद्दाख और नेफा का करीब 40 हजार मील का क्षेत्र चीन का है।

- 3 अप्रैल 1959 को तिब्बती लोगों के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा कई अन्य लोगों के साथ ल्हासा से भाग निकले और भारत आ गए। भारत ने उन्हें शरण दी और चीन बिदक गया।
- इसके पश्चात् चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया। उसने सितंबर 1959 में मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार कर दिया। बीजिंग ने सिक्किम और भूटान के करीब 50 हजार वर्ग मील के इलाके पर दावा ठोंक दिया था।
- 19 अप्रैल 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और झोउ के बीच नई दिल्ली में मुलाकात हुई।
- फरवरी 1961 में चीन ने सीमा विवाद पर चर्चा से मना कर दिया और भारतीय सीमा के पश्चिमी सेक्टर में घुस आया।
- नवम्बर १९६२ में चीनी सेना ने लद्दाख और तत्कालीन नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) में मैकमोहन रेखा के पार भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। चीन ने तीन-सूत्रीय सीजफायर फॉर्मूला सुझाया जो भारत ने मान लिया। चीन के इस आक्रमण के कारण द्विपक्षीय संबंधों में एक गंभीर झटका लगा।
- मार्च 1963 को चीन और पाकिस्तान में समझौता हुआ और पाक अधिकृत कश्मीर का लगभग 5080 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया गया।
- 1965 में चीन ने भारत पर सिक्किम-चीन सीमा पार करने का आरोप लगाया। नवम्बर में चीनी सैनिक दोबारा उत्तरी सिक्किम में घुसे। इसके बाद तनाव के चलते डिप्लोमेटिक चैनल बंद हो गया।
- 1974 में भारत ने अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया तो चीन ने उसका कड़ा विरोध किया।
- अप्रैल 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। चीन ने इसका भी विरोध किया।
- अप्रैल 1976 में, चीन और भारत ने पुनः राजदूत संबंधों को बहाल किया। जुलाई में केआर नारायणन को चीन में भारतीय राजदूत बनाया गया। द्विपक्षीय संबंधों में धीरे-धीरे सुधार हुआ।
- फरवरी 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की।
- 1988 में, भारतीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए, चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने "लुक फॉरवर्ड" के लिए सहमति व्यक्त की और सीमा के प्रश्न के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान की मांग करते हुए अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित किया।[1][2]
- 1991 में, चीन के सर्वोच्च नेता ली पेंग ने भारत का दौरा किया। 31 साल बाद चीन का कोई नेता भारत आया था।
- 1992 में, भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने चीन का दौरा किया। वह पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद से चीन का दौरा किया।
- सितम्बर 1993 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव चीन गए। इस यात्रा में सीमा शांति समझौता पर हस्ताक्षर हुए।
- अगस्त 1995 में दोनों देश ईस्टर्न सेक्टर में सुमदोरोंग चू घाटी से सेना पीछे हटाने को राजी हुए।
- नवंबर 1996 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन भारत आए। इस यात्रा में भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य क्षेत्र में विश्वास-निर्माण उपायों पर समझौता पर हस्ताक्षर हुए।
- मई 1998 में भारत के दूसरे परमाणु परीक्षण का भी चीन ने विरोध किया।
- अगस्त 1998 में ही लद्दाख-कैलाश मानसरोवर रूट खोलने पर आधिकारिक रूप से बातचीत शुरू हुई।

- जब करगिल युद्ध हुआ तो चीन ने किसी का साथ नहीं दिया। युद्ध खत्म होने पर चीन ने भारत से दलाई लामा की गतिविधियां रोकने को कहा ताकि द्विपक्षीय संबंध सुधरें।
- नवम्बर 1999 में सीमा विवाद सुलझाने को भारत-चीन के बीच दिल्ली में बैठकें हुईं।
- जनवरी 2000 में 17वें करमापा ला चीन से भागकर धर्मशाला पहुंचे और दलाई लामा से मिले। बीजिंग ने चेतावनी दी कि करमापा को शरण दी गई तो 'पंचशील' का उल्लंघन होगा। दलाई लामा ने भारत को चिट्ठी लिख करमापा को सुरक्षा मांगी।
- 1 अप्रैल 2000 को भारत और चीन ने राजनयिक सम्बन्धों की 50वीं बर्षगाँठ मनाई।
- जनवरी 2002 में चीनी राष्ट्रपति झू रोंगजी भारत आए।
- 2003 में, भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने चीन-भारत संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए, और भारत-चीन सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि बैठक तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए।
- अप्रैल 2005 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति वेन जियाबाओ बैंगलोर आए।
- 2006 में नाथू ला दर्रा खोला गया जो कि 1962 के युद्ध के बाद से बन्द था।
- 2007 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह कहकर वीजा नहीं दिया था कि अपने देश में आने के लिए उन्हें वीजा की जरूरत नहीं है।
- 2009 में जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह अरुणाचल गए तो चीन ने इसपर भी आपत्ति जताई।
- जनवरी 2009 को मनमोहन चीन पहुंचे। दोनों देशों के बीच व्यापार ने 50 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया।
- नवंबर 2010 में चीन ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए स्टेपल्ड वीजा जारी करने शुरू किए।
- अप्रैल 2013 में चीनी सैनिक LAC पार कर पूर्वी लद्दाख में करीब 19 किलोमीटर घुस आए। भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ा।
- जून 2014 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए और भारतीय समकक्ष सुषमा स्वराज से मिले। उसी महीने तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी पांच दिन के दौरे पर गए थे। जुलाई 2014 में भारतीय सेना के तत्कालीन चीफ बिक्रम सिंह तीन दिन के लिए बीजिंग दौरे पर गए थे। उसी महीने ब्राजील में हुई BRICS देशों की बैठक में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने करीब 80 मिनट तक बातचीत की थी।
- सितंबर 2014 में शी जिनपिंग भारत आए। नरेन्द्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर अहमदाबाद में उनका स्वागत किया था। चीन ने पांच साल के भीतर भारत में 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा के निवेश का वादा किया।
- फरवरी 2015 में सुषमा ने चीन की यात्रा की और वहां पर शी जिनपिंग से मिलीं।
- मई 2015 में प्रधानमंत्री मोदी का पहला चीन दौरा हुआ। अक्टूबर में जिनपिंग और मोदी की मुलाकात गोवा में BRICS देशों की बैठक में हुई।
- जून 2017 में भारत को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) का पूर्ण सदस्य बनाया गया। मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात की और इसके लिए उनका धन्यवाद किया।

- 2018 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वुहान, चीन और महाबलीपुरम, भारत में भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक अनौपचारिक बैठक की।

निष्कर्ष

पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि के साथ, कई भारतीय कंपनियों ने चीन में अपने भारतीय और बहुराष्ट्रीय ग्राहकों दोनों की सेवा के लिए चीनी परिचालन स्थापित करना शुरू कर दिया है। चीन में प्रतिनिधि कार्यालयों, पूर्ण स्वामित्व वाले विदेशी उद्यमों या चीनी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में काम कर रहे भारतीय उद्यम विनिर्माण (फार्मास्युटिकल्स, रिफ्रैक्टरीज, लैमिनेटेड ट्यूब, ऑटो-कंपोनेंट्स, पवन ऊर्जा, आदि), आईटी और आईटी-सक्षम सेवाओं (सहित) में हैं। आईटी शिक्षा, सॉफ्टवेयर समाधान, और विशिष्ट सॉफ्टवेयर उत्पाद), व्यापार, बैंकिंग और संबद्ध गतिविधियां।

जबकि भारतीय व्यापारिक समुदाय मुख्य रूप से ग्वांगझू और शेनझेन जैसे प्रमुख बंदरगाह शहरों तक ही सीमित है, वे बड़ी संख्या में उन जगहों पर भी मौजूद हैं जहां चीनियों ने गोदामों और थोक बाजारों जैसे कि यिवू की स्थापना की है। अधिकांश भारतीय कंपनियों की उपस्थिति शंघाई में है, जो चीन का वित्तीय केंद्र है; जबकि कुछ भारतीय कंपनियों ने बीजिंग की राजधानी में कार्यालय स्थापित किए हैं। चीन में कुछ प्रमुख भारतीय कंपनियों में डॉ रेड्डीज लैबोरेट्रीज, अरबिंदो फार्मा, मैट्रिक्स फार्मा, एनआईआईटी, भारत फोर्ज, इंफोसिस, टीसीएस, एपीटेक, विप्रो, महिंद्रा सत्यम, एस्सेल पैकेजिंग, सुजलॉन एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सुंदरम फास्टनर, महिंद्रा और शामिल हैं। महिंद्रा, टाटा संस, बिनानी सीमेंट्स, आदि। बैंकिंग के क्षेत्र में, दस भारतीय बैंकों ने चीन में परिचालन स्थापित किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (शंघाई), बैंक ऑफ इंडिया (शेन्ज़ेन), केनरा बैंक (शंघाई) और बैंक ऑफ बड़ौदा (गुआंगज़ौ) के शाखा कार्यालय हैं, जबकि अन्य (पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन) बैंक ऑफ इंडिया, आदि) के प्रतिनिधि कार्यालय हैं। पीएसयू बैंकों के अलावा, एक्सिस, आईसीआईसीआई जैसे निजी बैंकों के भी चीन में प्रतिनिधि कार्यालय हैं।

भारतीय दूतावास के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लगभग 100 चीनी कंपनियों ने भारत में कार्यालय/संचालन स्थापित किए हैं। मशीनरी और बुनियादी ढांचे के निर्माण के क्षेत्र में कई बड़ी चीनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों ने भारत में परियोजनाएं जीती हैं और भारत में परियोजना कार्यालय खोले हैं। इनमें सिनोस्टील, शौगांग इंटरनेशनल, बाओशन आयरन एंड स्टील लिमिटेड, सैनी हेवी इंडस्ट्री लिमिटेड, चोंगकिंग लाइफन इंडस्ट्री लिमिटेड, चाइना डोंगफैंग इंटरनेशनल, चीन हाइड्रो कॉर्पोरेशन आदि शामिल हैं। कई चीनी इलेक्ट्रॉनिक, आईटी और हार्डवेयर निर्माण कंपनियां भी भारत में परिचालन करती हैं। इनमें हुआवेई टेक्नोलॉजीज, जेडटीई, टीसीएल, हायर आदि शामिल हैं। बड़ी संख्या में चीनी कंपनियां बिजली क्षेत्र में ईपीसी परियोजनाओं में शामिल हैं।

इनमें शंघाई इलेक्ट्रिक, हार्बिन इलेक्ट्रिक, डोंगफैंग इलेक्ट्रिक, शेनयांग इलेक्ट्रिक आदि शामिल हैं। चीनी ऑटोमोबाइल प्रमुख बीजिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन (BAIC) ने हाल ही में पुणे में एक ऑटो प्लांट में 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की योजना की घोषणा की है। झिंजियांग स्थित ट्रांसफार्मर निर्माता टीबीईए ने गुजरात में एक विनिर्माण सुविधा में निवेश करने की योजना बनाई है। प्रीमियर वेन की भारत यात्रा के दौरान, हुआवेई ने चेन्नई में एक दूरसंचार उपकरण निर्माण सुविधा में निवेश करने की योजना की घोषणा की।

भारत-चीन आर्थिक संबंध दोनों देशों के बीच रणनीतिक और सहयोगात्मक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कई संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। आर्थिक संबंधों और व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (जेईजी) और भारत-चीन रणनीतिक और आर्थिक संवाद (एसईडी) पर भारत-चीन संयुक्त आर्थिक समूह के अलावा, 2006 से दोनों देशों के बीच एक वित्तीय वार्ता भी हो रही है।

अप्रैल 2005 में चीनी प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत और चीन के बीच वित्तीय वार्ता के शुभारंभ पर समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों पक्षों ने तब से सफलतापूर्वक वित्तीय वार्ता आयोजित की है। संवाद के अंत में एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए और उसे जारी किया गया। बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने वैश्विक वृहद आर्थिक स्थिति और नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्तमान जोखिमों और संकट के बाद रिकवरी चरण में भारत और चीन की भूमिका का विशेष उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में सुधार और मजबूत, टिकाऊ और संतुलित विकास के लिए रूपरेखा सहित जी20 मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

संदर्भ

- भारत-चीन संबंध- चुनौतियाँ और उभरते मुद्दे
- भारत चीन संबंध: एक नज़र में

- चीन की चिढ़ और भारत दृढ़, पड़ोसियों को साधकर ड्रैगन को घेरने की कोशिश (जागरण)
- चीन और भारत की हकीकत (पड़ताल)
- भारत के साथ युद्ध चीन को बर्बाद कर देगा, ये हैं 5 कारण
- क्या है चीन की भारत नीति?
- भारत-चीन संबंध पर निबन्ध
- विदेश मामलों की स्थायी समिति द्वारा 4 सितंबर, 2018 को "डोकलाम, सीमा-स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सहयोग सहित चीन-भारत सम्बन्ध" पर रपट
- भारत-चीन जल संबंधों के भविष्य की राह
- क्या पूर्ण रूप से चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया जा सकता है?